



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 550]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2010/आश्विन 8, 1932

No. 550]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2010/ASVINA 8, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010

सं. 99/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 795(अ).— चूंकि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष 854011 के अंतर्गत आने वाले मलेशिया, थाईलैंड, चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया आर पी (जिसे इसके बाद पात्र देश कहा गया है) में उत्पन्न या वहां से निर्यातित कैथोड रे कलर टेलीविजन पिकचर ट्यूब के आयात के मामले में नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, शुद्धिपत्र सं. 14/8/2007-डी जी ए डी, दिनांक 17 अप्रैल, 2009 के साथ पठित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-I, दिनांक 17 फरवरी, 2009 को प्रकाशित अधिसूचना सं.14/8/2007-डी जी ए डी, दिनांक 17 फरवरी, 2009 के अपने अंतिम जांच निष्कर्षों में इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि,-

(क) पात्र देशों से उत्पन्न हो रहे आयात प्रतिपाटित मूल्यों पर हो रहे हैं और इससे घरेलू उद्योग को पर्याप्त क्षति पहुंची है;

(ख) पात्र देशों से पात्र आयातों की बाजार के हिस्से में वृद्धि से घरेलू उद्योग की बाजार के हिस्से में कमी ने घरेलू उद्योग को मांग में वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री बढ़ाने से रोका है;

(ग) कीमतों में भारी कटौती और प्रतिपाटित आयात की मात्रा में भारी वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग के निष्पादन पर लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर प्रतिफल की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(घ) पात्र देशों से प्रतिपाटित आयात की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि (निरपेक्ष शब्दों में तथा मांग में हिस्से के संदर्भ में) के कारण बाजार में घरेलू उद्योग के हिस्से में भारी गिरावट हुई है;

और चूंकि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम जांच निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने पात्र माल पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि.337 (अ), दिनांक 15 मई, 2009 के जरिए प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.50/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मई, 2009 के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगा दिया था;

और चूंकि मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लि. (कोरिया आर पी से उत्पादक और निर्यातक) (जिसे इसमें पात्र पक्षकार कहा गया है) ने अपने द्वारा किए गए निर्यात के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिपाटित माल की पहचान, मूल्यांकन और प्रतिपाटन शुल्क की वसूली तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 के नियम 22 के निबंधनों के तहत समीक्षा का अनुरोध किया था तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-I, दिनांक 13 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित नई नौप्रेषण समीक्षा अधिसूचना सं. 15/10/2009-डी जी ए डी, दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के तहत समीक्षा पूरी होने तक पात्र पक्षकार द्वारा भारत में पात्र माल के सभी निर्यात की अनंतिम मूल्यांकन की अनुशंसा की थी;

और चूंकि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की उपर्युक्त सिफारिश के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि. 922 (अ), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं.144/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 जारी करके आदेश दिया था कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास कथित समीक्षा के लंबित रहने तक पात्र पक्षकार द्वारा पात्र माल के निर्यात के भारत में आयात किए जाने पर, समीक्षा पूरी होने पर अनंतिम मूल्यांकन किया जाएगा;

और चूंकि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने नई नौप्रेषण समीक्षा पूरी कर ली है और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-I, दिनांक 19 जुलाई, 2010 में अधिसूचना सं. 15/10/2009-डी जी ए डी, दिनांक 19 जुलाई, 2010 के तहत प्रकाशित अंतिम जांच निष्कर्षों में निष्कर्ष निकाला है कि,-

- (i) आवेदक द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिपाटन मार्जिन की नए सिरे से निर्धारण की जरूरत नहीं है।
- (ii) इसके बजाय, आवेदक को उसी स्तर की प्रतिपाटन मार्जिन और परिणामस्वरूप प्रतिपाटन शुल्क के भुगतान का बेंचमार्क दिए जाने की जरूरत है जो मैसर्स एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज कोरिया कम्पनी लि. कोरिया को दी गयी थी ।

(iii) मैसर्स एल जी फिलिप्स डिस्प्लेज कोरिया कम्पनी लि., कोरिया विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता हुए बिना, यद्यपि पुष्टरूप से, कोरिया में अलग असंबद्ध कानूनी सत्ता बनी हुई है।

और शुल्क सारणी में निम्नलिखित संशोधनों की सिफारिश की है:

(i) क्र.सं.6 के सामने, कालम (6) में उत्पादक का नाम संशोधित किया जाए जिससे वह मैसर्स सोलर डिस्प्लेज कम्पनी लि. पढ़ा जाए।

(ii) क्र.सं.6 के सामने, कालम (7) में निर्यातक का नाम संशोधित किया जाए जिससे वह मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लि./या और मैसर्स एल जी इंटरनेशनल (एस पोर) पी टी ई लि., सिंगापुर पढ़ा जाए।

अतः अब, उपर्युक्त अंतिम परिणामों के आधार पर केन्द्र सरकार सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, मूल्यांकन तथा प्रतिपादन शुल्क की वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18, 20 और 22 के साथ पठित उपर्युक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9ए की उपधारा (1) और उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि.337 (अ) दिनांक 15 मई, 2009 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.50/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मई, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश:-

उपर्युक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम सं.6 के सामने कालम (6) की प्रविष्टियों को, "मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लि." से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम सं.6 के सामने कालम (7) की प्रविष्टियों को "मैसर्स मेरीडियन सोलर एंड डिस्प्ले कम्पनी लि. या/ और मैसर्स एल जी इंटरनेशनल (एस पोर) पी टी ई लिमिटेड सिंगापुर" से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 354/87/2008-टी.आर.यू. (पार्ट-1)]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं.50/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 15 मई, 2009 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में सा.का.नि.337 (अ) दिनांक 15 मई, 2009 के तहत प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2010

No. 99/2010-Customs

G.S.R. 795(E).— Whereas, in the matter of import of Cathode Ray Colour Television Picture Tubes (hereinafter referred to as the subject goods), falling under sub-heading 8540 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) originating in, or exported from Malaysia, Thailand, China PR and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority, in its final findings vide notification No. 14/8/2007-DGAD, dated the 17th February, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I, dated the 17th February, 2009, read with the corrigendum No. 14/8/2007-DGAD, dated the 17th April 2009, had come to the conclusion that, -

(a) imports originating in the subject country are taking place at dumped prices and the same had caused material injury to the domestic industry;

(b) decline in market share of domestic industry as a consequence of increase in market share of subject imports from the subject country prevented the domestic industry from increasing their sales commensurate to growth in demand;

(c) significant price-undercutting and substantial increase in the volume of dumped imports adversely affected the performance of the domestic industry in terms of profits, cash flow, and return on investment;

(d) significant increase in volume of dumped imports from the subject country (both in absolute terms as well as in relation to the share in demand) had resulted in significant decline in market share of the domestic industry;

And whereas, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2009-Customs, dated the 15th May, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R. 337(E), dated the 15th May, 2009;

And whereas, M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd., (Producer or Exporter from Korea RP) (herein referred to as "the subject party") had requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 in respect of exports made by them, and the designated authority vide new shipper review notification no. 15/10/2009-DGAD dated the 13th November 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1 dated the 13th November 2009 recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the subject party in to India till the completion of the review;

And whereas, on the basis of the aforesaid recommendation of the designated authority, the Central Government had issued notification No. 144/2009-Customs on the 23rd Dec 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 922(E), dated the 23rd Dec 2009 ordering that pending the outcome of the said review by the designated authority the subject goods exported by the subject party when imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed;

And whereas, the designated authority has completed the new shipper review and in its final findings *vide* Notification No. 15/10/2009-DGAD dated the 19th July 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th July 2010 has come to the conclusion that,-

(i) individual dumping margin in respect of exports made by the applicant is not required to be determined a fresh.

(ii) instead, the applicant is required to be given the same level of dumping margin and consequently the benchmark for payment of anti dumping duties as was given to M/s. LG Philips Displays Korea Co. Ltd. Korea.

(iii) M/s. LG Philips Displays Korea Co. Ltd., Korea continues as a separate unrelated legal entity in Korea, however confirmedly, without being in the manufacture of the Product under Consideration.

And has recommended following amendments in the duty Table:

(i) against Serial No. 6, in column (6), the name of the Producer may be amended to read as M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd.

(ii) against serial no. 6, in column No. (7), the name of the exporter may be amended to read as M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd. or/ and M/s LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act read with rules 18, 20 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings, hereby makes the following amendments, in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2009-Customs, dated the 15th May, 2009 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 337(E), dated the 15th May, 2009, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) Against Sl.No.6, for the entries in column (6), "M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd." shall be substituted.

(ii) Against Sl.No.6, for the entries in column (7), "M/s. Meridian Solar & Display Company Ltd. or/ and M/s LG International (S'Pore) Pte. Limited, Singapore" shall be substituted.

[F. No. 354/87/2008-TRU (Pt. I)]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2009-Customs, dated the 15th May, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 337(E), dated the 15th May, 2009.

3830 GI/10-2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2010

सं. 100/2010-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 796(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्वारा, ऐसे माल को, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आते हैं तथा जब उनको लद्दाख क्षेत्र में राहत कार्यों के उद्देश्य के लिये लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद को दान में दिये जाने के प्रयोजन के लिये लिली फ़ो फाउण्डेशन द्वारा भारत में आयात किया जा रहा हो, निम्नलिखित से छूट प्रदान करती है:-

(क) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उसपर लगने वाले सम्पूर्ण सीमा शुल्क से; और

(ख) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस पर लगने वाले सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से ;

बशर्ते कि,-

(i) सुसंगत दस्तावेजों की निकासी (क्लियरेंस) के वक्त आयातकर्त्ता द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि यह माल लद्दाख क्षेत्र में राहत कार्यों के लिये लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद को दान में दिये जाने के लिए है और इसके लिये कोई प्रभार नहीं लिया जायेगा; और

(ii) आयातकर्त्ता को उप आयुक्त या सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसी स्थिति हो, के समक्ष, उक्त माल के आयात की तारीख से छः महीने के भीतर या ऐसी बढ़ी हुई अवधि के भीतर जिसे उक्त अधिकारी ने अनुमति दी हो, लेकिन आयात की तारीख से एक साल के बाद नहीं, लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी (सी ई ओ) से प्राप्त एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त माल को उपर्युक्त उद्देश्य के लिये लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वतीय विकास परिषद को दान में दे दिया गया है।

2. उक्त अधिसूचना 30 सितम्बर, 2011 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगी ।

[फा. सं. 354/180/2010-टी.आर.यू.]

के. एस. वी. वी. प्रसाद, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2010

No. 100/2010-Customs

G.S.R. 796(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) when imported into India by the Lille Fro Foundation and intended for donation to the Ladakh Autonomous Hill Development Council for the purposes of the relief operations in the Ladakh region from,—

- (a) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the said Customs Tariff Act; and
- (b) the whole of additional duty of customs leviable thereon under the section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the following conditions, namely:—

- (i) that it is certified by the importer on the relevant clearance documents that the goods are intended to be donated to the Ladakh Autonomous Hill Development Council for the purposes of the relief operations in the Ladakh region without making any charge therefor; and
- (ii) that the importer produces before the Deputy Commissioner or the Assistant Commissioner of Customs, as the case maybe, within six months from the date of importation of the said goods or within such extended period as the said officer may allow, but not later than one year from the date of importation, a certificate from the Chief Executive Officer of Ladakh Autonomous Hill Development Council that the said goods have been donated to the Ladakh Autonomous Hill Development Council for use for the aforesaid purpose.

2. This notification shall remain in force upto and inclusive of the 30th September, 2011.

[F. No. 354/180/2010-TRU]

K. S. V. V. PRASAD, Under Secy.